RAJYA SABHA

Tuesday, the 4th March, 2008/14 *Phalguna,* 1929 (*Saka*)

The House met at eleven of the clock,

MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

मध्य प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों की स्थापना

81. **श्रीमती माया सिंह:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क) मध्य प्रदेश में अभी कितने विमानपत्तन सक्रिय हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं;

ख) मध्य प्रदेश की जनता को आवागमन की सुविधा प्रदान करने तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नए विमानपत्तनों के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

ग) यदि हां, तो इन विमानपत्तनों का निर्माण-कार्य कब तक प्रारंभ कर दिया जाएगा?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल्ल पटेल): (क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

(क) से (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास मध्य प्रदेश में चार हवाई अड्डों यथा भोपाल, खजुराहो, इन्दौर तथा जबलपुर का स्वामित्व तथा प्रबंधन है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास ग्वालियर में एक सिविल एन्क्लेव का भी प्रबंधन है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की 35 गैर मेट्रो हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण परियोजना के अंतर्गत इन्दौर तथा खजुराहो के हवाई अड्डों को स्तरोन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए चुना गया है। उक्त 3 हवाईअड्डों के आधुनिकीकरण का कार्य 2009 के मध्य तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

Setting up of international airports in Madhya Pradesh

*81. SHRIMATI MAYA SINGH: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) the number of airports operating in Madhya Pradesh at present alongwith the locations thereof;

(b) whether any proposal is under consideration of Government for construction of new airports of international standard in order to extend facility for movement of the people of Madhya Pradesh as also to promote tourism; and

(c) if so, by when the construction work of these airports would be started?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI PRAFUL PATEL): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) Airports Authority of India (AAI) owns and manages four airports namely, Bhopal, Khajuraho, Indore and Jabalpur in Madhya Pradesh. AAI also manages a Civil Enclave at Gwalior. The airports at Bhopal, Indore and Khajuraho have been taken up for upgradation/modernisation under the 35 Non-Metro airports modernisation project of AAI. The modernisation work at the said three airports is scheduled for completion by mid 2009.

श्रीमती माया सिंह: सभापति जी, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में हज यात्री जाते हैं, पर्यटक मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में आते हैं और मध्य प्रदेश सरकार भोपाल एयरपोर्ट के लिए

*Original notice of the question was received in Hindi.

5250 लाख रुपए, इंदौर एयरपोर्ट के लिए 750 लाख रुपए और खुजराहो एयरपोर्ट के लिए 244 लाख रुप चुकी है, लेकिन प्रगति कुछ नहीं दिखाई दे रही है। मैं केन्द्र सरकार से जानना चाहती हूं कि मेरे जो सवाल उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के चार हवाई अड्डों का स्वामित्व और प्रबंधन भारतीय विमानपत्तन प्राधिक है, इसलिए मैं जानना चाहती हूं कि केन्द्र सरकार ने इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है, तो बताएं लिए बजट में कोई एलोकेशन किया है या आपका कोई टाइम प्लान है, जिसके तहत इन चार हवाई अड्डों, जैसा कहा है, खुजराहो, इंदौर, भोपाल और जबलपुर के प्रबंधन के लिए और इसके अपग्रेड के लिए आप काम पूरा

श्री प्रफुल्ल पटेल: धन्यवाद माया जी, आपको हज यात्रियों की याद आई ...(व्यवधान)...

श्रीमती माया सिंह: हम तो हमेशा याद करते हैं ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Please proceed with the answer. (*Interruptions*)

श्री प्रफुल्ल पटेल: मैं धन्यवाद दे रहा हूं, मैंने कुछ कहा नहीं ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Please proceed with the answer. (*Interruptions*)

श्रीमती माया सिंह: हज यात्रियों के लिए flight facilities दी हैं या नहीं?

श्री प्रफुल्ल पटेल: Sir, I am only thanking the hon. Member. I am not trying to say anything or imply any motives. आपने सही फरमाया कि मध्य प्रदेश के जो चार हवाई अड्डे हैं, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास हैं, उनका अपग्रेडेशन करने का एक सिलसिला बहुत दिनों से चल रहा है और ऐसा नहीं है कि सिलसिला सिर्फ चल रहा है या सोच की अवस्था में है, बल्कि उसके कई पहलुओं पर implementation का काम भी फिलहाल जारी है। सबसे बड़ी समस्या, न केवल मध्य प्रदेश के लिए बल्कि सभी राज्यों के लि हमको महसूस हो रही है, वह यह है कि जिन हवाई अड्डों का निर्माण पहले हुआ, अब उनमें विस्तार करने क आया है। हर जगह की अपेक्षाएं बढ़ी हैं, वहां की जरूरतें बढ़ी हैं और उसके अनुरूप हम जो चाहते हैं उसके लिए जो सबसे महत्व की होती है, क्योंकि उसके बिना तो विकास हो ही नहीं सकता, एक्सपेंशन हो नही सकता है, उसके हमको राज्य सरकारों से सहायता की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश सरकार के साथ भी कई वर्षों से इस बारे में बातचीत चलती रही। कुछ उनकी भी मर्यादाएं थीं क्योंकि सारी जमीन ऐसी ही नहीं है कि राज्य सरकार के दावे में होती है, कहीं acquisition करना पड़ता है, कहीं और एजेंसी उसमें involve होती है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ ही समय पहले यानी पिछले वर्ष के कुछ महीने पूर्व की बात बोल रहा हूं, वहां भोपाल में उन्होंने हमें कुछ जमीन उपलब्ध करा कर दी है, इंदौर में भी कुछ जमीन उपलब्ध करा कर दी है। पूरी मात्रा में जो चाहिए, वह नहीं मिली है, लेकिन निश्चित काम को शुरूआत करने के लिए, काम को आगे बढ़ाने के लिए अब हमारे पास भूमि भोपाल और इंदौर में विशेष करके प्राप्त हुई है। आपको मैं यह कहना चाहूंगा कि भोपाल में जो आज तक की सबसे बड़ी समस्या रही है, वह यह है कि भोपाल में नौ हजार फीट का रनवे बनाने के लिए भूमि नहीं थी और छोटे र की वजह से, आप जो विशेषकर हज का प्रश्न पूछ रही हैं, इंदौर और भोपाल से हज की flight इसलिए नहीं च जा सकती थी क्योंकि रनवे की मर्यादा की वजह से बड़े हवाई जहाज वहां नहीं उतर सकते थे। भोपाल में अभी न रनवे का काम अवार्ड कर दिया है, वहां नौ हजार फीट का रनवे इस वर्ष के अंत तक या अगले साल के शुरू तक पूरा हो जाएगा। इंदौर में भी नौ हजार फीट के रनवे का काम हमने अवार्ड कर दिया है। इतना ही नहीं, हमारे non-metro airports की जो पूरे भारत में हवाई अड्डों का विकास करने की स्कीम है, आपको इस बात जानकर खुशी होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश के 35 हवाई अड्डों में से 3 हवाई अड्डे-भोपाल, इंदौर और खुजराहो, क का हमने non-metro scheme में समावेश किया है। इसके अलावा थोड़ी राशि की जानकारी भी अंदाजन मैं चाहता हूं, क्योंकि works ongoing होते हैं, लेकिन साधारणत: भोपाल में करीब 205 करोड़ का काम टर्मि runway और बाकी अपग्रेडेशन का लिया जा रहा है। इंदौर में करीब 230 करोड़ का और खुजराहो में 100 करोड़ का काम लिया जा रहा है, तो राशि का इसमें कोई सवाल नहीं है। जितनी राशि की आवश्यकत वह उपलब्ध होगी, लेकिन जहां तक मध्य प्रदेश के हवाई अड्डों का सवाल है, तीनों हवाई अड्डों के अच्छे भूतलीकरण और अपग्रेडेशन का काम निश्चित तौर पर आगे आप लोग देखेंगे।

श्रीमती माया सिंह: सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहती हूं कि खुजराहो में विश्व प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर हैं और वहां पर हवाई अड्डा नजदीक होने की वजह से जो कम्पन होता है, उससे उन प्राचीन मंदिरों को क्षति पहुंच रही है। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि आपने उसकी क्या चिंता की है? क्या आपने ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है कि उन मंदिरों को क्षति न पहुंचे? उसके नजदीक ही या थोड़ी दूरी पर airport बनाने के लिए उसकी वैकल्पिक व्यवस्था का कोई प्रस्ताव क्या आपने मध्य प्रदेश सरकार को भेजा है या उनसे बातचीत की है? इसके साथ-साथ मेरा एक प्रश्न यह भी है कि जबलपुर में night landing facility नहीं है और जबलपुर में बेड़ाघाट आदि पर्यटन के स्थान हैं, वहां पर भी बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचते हैं, लेकिन वहां night landing facility नहीं है, तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि उसके लिए वे क्या कर रहे हैं?

श्री प्रफुल्ल पटेल: आपने जहां तक खुजराहो airport की बात की, वहां पर हमारे प्राचीन मंदिर हैं, जिनका एक चर्ल्ड हैरिटेज साइट में समावेश है और उनकी रक्षा करना, उनका ध्यान रखना, यह हम सबके लिए बहुत आवश्यक है और क्योंकि यह बात हमारी जानकारी में भी लाई गई थी, तो हमने National Physical Laboratories को यह कहा था कि वह एक स्टडी करे कि हवाई जहाजों के आने-जाने से हमारे इन मंदिरो को कुछ नुकसान होता हो, तो उसका कुछ निश्चित ध्यान रखा जा सकता है या कोई और प्रोसीजर हम बदलें, क्योंकि उनके हिसाब से आया है कि फिलहाल ऐसा कुछ उनके ध्यान में नहीं आया है कि हवाई जहाजों के आने-जाने से कोई नुकसान वहां की वास्तु को हो रहा हो, इसलिए फिलहाल हम लोग इसमें ऐसा कोई और कदम नही लेना चाह रहे हैं, लेकिन यह भी मैं बताना चाहूंगा कि अभी फिलहाल वहां बहुत कम फ्लाइट्स आती-जाती हैं, अगर भविष्य में ज्यादा फ्लाइट्स के आने-जाने से वहां कुछ नुकसान हो, ऐसी अगर आपकी भावना है, तो हम लोगों ने ध्यान दिया है, लेकिन आगे भी हम अपने प्राधिकरण को कहेंगे कि इसके बारे में वह ध्यान रखे।

जहां तक जबलपुर का सवाल है, जबलपुर में भी night landing facility का, आने वाले समय में, उसके निर्माण का काम पूरा किया जाएगा। वैसे अधिकतम, देश के सारे हवाई अड्डे ठीक है कि पुराने समय में night landing सब जगह नहीं थी, लेकिन अब हमारी यह पॉलिसी है कि जितने भी operational हवाई अड्डे हैं, न केवल वे operational रहें, लेकिन उनमें आधुनिक यंत्र और साथ-साथ में night landing की सुविधा हर हवाई अड्डे में प्रदान करने का हमारा कार्यक्रम है और कोशिश है कि एकाध साल में हम इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे।

श्रीमती माया सिंह: मध्य प्रदेश में एक भी international airport नहीं है, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि उसका क्या कारण है?

MR. CHAIRMAN: You have asked your supplementaries. Mr. Shantaram Laxman Naik.

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Sir, acquisition of land for international airports is a serious issue which the Civil Aviation Ministry is facing. In Goa, when the issue of expansion of Dabolim airport came, the entire land is occupied by the Indian Navy. Sir. the land belongs to the Government of Goa. But, the Airports Authority of India is asking for more land from the Indian Navy, not from the Government of Goa! This is indirectly recognising the right of the Indian Navy. Whereas, the records and title shows that land belogns to the Government of Goa. As a result, the Ministry had to spend a lot of time in getting land for expansion of airport. Sir, his Ministry should have taken up the issue with the Minisry of Defence saying that they should give up their right on land and should not claim that the land belongs to them so that land is easily made available for expansion of airport. Therefore, at this stage, I would like to know the status of the land that you have wrongly asked from the Defence Ministry rather than asking from the Goa Government.

SHRI PRAFUL PATEL: Sir, first and foremost, this does not pertain to the main question because we are talking about airports in Madhya Pradesh. However, since I have firsthand knowledge of this problem raised by the hon. Member, I will answer it. The Goa airport, *per se,* is airport of the Indian Navy, and we are only running a civil enclave there. Of course, we

have had many issues, from time to time, because Goa seriously requires a new airport. But, in the meantime, this airport needs to be upgraded because it attracts very high-end tourism. In fact, it attracts all categories of tourism. Goa has become a very popular destination worldwide, as well as, within the country. I can assure the hon. Member that there is no question of the Government of India or the Ministry of Civil Aviation talking to the wrong agencies for the purpose of land. We will, certainly, be talking to whoever is the owner of the land. In this case, we will be talking to the Indian Navy, as well as, the Goa Government in case of some additional land which is outside the territory of the airport.

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Even the encroachers are there.

SHRI PRAFUL PATEL: I cannot answer about encroachments. But, I can, certainly, tell you that in this case I have personally conducted many meetings in my office with all agencies. I have met the Navy Chief. I have met the Defence Secretary. My officials have been holding meetings. I have met the concerned authorities in the Government of Goa on several occasions. Of course, this has gone a little bit round and round. I can, certainly, feel that there would be some resolution in the near future. I would also urge you to support us and take up this issue at the local level also and try to see that this land is made available. We are ready to build a very good terminal there. We have all the resources to do so. But, at the same time, in the absence of land, this issue is something which has not yet been resolved.

श्री राम नारायण साहू: सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि लखनऊ, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन चुका है, वहां से केवल दुबई और शारजाह के लिए ही हवाई जहाज जाते हैं। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है। क्या मंत्री जी इस संबंध में कुछ विचार कर रहे हैं कि वहां से दूसरे देशों के लिए और विमान चलाए जाएं, क्योंकि जो लोग अन्य जगहों पर जाना चाहते हैं उन्हें इसके लिए पहले दिल्ली जाना पड़ता है — पूरे उत्तर प्रदेश और उसके आस-पास के लोगों को इसके लिए दिल्ली जाना पड़ता है। सर, लखनऊ उत्तर प्रदेश की केपिटल है और नॉर्दन इंडिया के बड़े शहरों में दिल्ली के बाद लखनऊ दूसरे नम्बर पर है।

श्री सभापति: आप सवाल पूछ लें।

श्री राम नारायण साहू: सर, मैंने सवाल पूछ लिया है। मैं सिर्फ बता रहा था कि यह क्यों जरूरी है। मेरा सवाल यही है कि अभी केवल शारजाह और दुबई के लिए वहां से प्लेन्स जा रहे हैं तो क्या मंत्री जी का इसे आगे बढ़ाने का विचार है?

श्री प्रफुल्ल पटेल: सवाल मध्य से उत्तर की दिशा में चला गया है। ...(**व्यवधान**)... सर, माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि लखनऊ से हवाई सेवाओं में विकास और होगा या नहीं होगा और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विकास होगा या नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले तीन-चार वर्षों में हवाई क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इस संबंध में हम लोगों को किसी को इससे असहमति होनी चाहिए। इसमें निश्चित रूप से वृद्धि हो रही है। हर राज्य से, हर बड़े शहर में सबकी अपेक्षा है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं बढ़ती जाएं। यह सिलसिला जारी है। नए-नए एयरपोर्ट्स से अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं को बढ़ाने का हमने प्रयास किया है। लखनऊ का वैसे भी नॉन मेट्रो एयरपोर्ट की केटॉगरि में समावेश है, बड़े एयरपोर्ट्स की केटॉगरि में समावेश होता ही है, आगे इसमें और विकास होगा। मुझे लगता है कि जैसे इस संबंध में वहां के लोगों की अपेक्षाएं होंगी, हमें हवाई सेवाओं को बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री विक्रम वर्मा: माननीय सभापति महोदय, अभी सेवाएं बढ़ाने की बात तो हुई, चूंकि स्वामित्व और प्रबंधन भी सब इनके पास है, लेकिन सुरक्षा के संबंध में माननीय मंत्री जी ने कोई विशेष बात नहीं बताई। अभी हाल ही में दो दुर्घटनाएं होते-होते बची हैं, जिसमें कानपुर में रनवे पर नील गाए आ गई थी, परंतु प्लेन बड़ी मुश्किल से बचा, नहीं तो कितनी बड़ी दुर्घटना होती। कल दिन भर टी०वी० पर दिखाया जा रहा था कि मुम्बई एयरपोर्ट पर एक साथ दो प्लेन लैंडिंग हो रहे थे। अगर वहां पर भी कॉशस नहीं होता तो कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती। तो यह सारी स्थिति है। आप विकास की बात कर रहे हैं कि हम इतनी फ्लाइट्स बढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि स्वामित्व आपका है, प्रबंधन आपका है, तो सुरक्षा के संबंध में आप क्या कर रहे हैं?

मेरा "बी" प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जाकर दिल्ली-जबलपुर-भोपाल की फ्लाइट चालू की थी, जो कि फिर बन्द पड़ी है। यह दो-चार दिन चलती है और फिर दो महीने बंद हो जाती है। तो उसको धीमे चलाने के संबंध में आप क्या करने जा रहे हैं, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं?

श्री प्रफुल्ल पटेल: जहां तक आपके पहला प्रश्न सुरक्षा के संबंध में है, मुझे नही लगता कि जिसको हम एक ऐसा मुद्दा बनाएं क्योंकि यह टेक्नीकल बातें हैं। एक हवाई जहाज उतर रहा है और दूसरे हवाई जहाज ने अगर रनवे पर टेक-ऑफ नहीं किया है तो उसमें सुरक्षा के प्रावधान हैं, क्योंकि यह तो रोज का सिलसिला है, रोज रनवे पर वही हवाई जहाज उतरता है ...(**व्यवधान**)... मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं ...(**व्यवधान**)...

श्री विक्रम वर्मा: आप एजिटेट क्यों हो रहे हो कि यह रोज का सिलसिला है। इसमें एजिटेट होने की क्या बात है। ...(**व्यवधान**)...

SHRI PRAFUL PATEL: I could have said that I could not answer this question.

MR. CHAIRMAN: Please, please. ...(*Interruptions*)... Let the hon. Minister proceed. ...(*Interruptions*)...

SHRI PRAFUL PATEL: You should listen. ...(*Interruptions*)... You should listen. Ultimately, it is a ...(*Interruptions*)... If you are raising an issue of safety unless you listen how can I explain to you? This is not an issue of giving money to 'x' airport of 'y' airport. Ultimately, everybody sitting in this House and outside is concerned about flying and safety of flying.आप कह रहे हैं कि on the same runway a plane was detected and the other plane could not land. We are all flying everyday, on the same runway planes land and takeoff. If a plane has not taken off on the time on the runway, which it was assigned to takeoff, the incoming plane is asked to go along. It is not something to be made an issue of safety. The person who is in the ATC Tower is aware. There are enough safeguards in the system. It is not that blindly an aircraft is coming in and landing. So, let us not make an issue of something and unnecessarily create a scare. After all, the people who are manning the ATC towers, let us not demoralise them. They are also, after all, people who are highly skilled. We are giving our entire future, our life, and security in their hands, let them not get the impression that we are all the time criticising them. That is all I am saying, nothing else. I am not trying to say that .... *(Interruptions)*... Of course, there are issues sometimes, which need urgent attention, and they are being looked at. Now, in this case of Neelgai, which you mentioned at Kanpur Airport, it is an Indian Air Force Airport. If suddenly due to some reason an animal strayed into the airport, how can we detect something because that is the job of the Indian Air Force? However, we have advised them and cautioned them that this is something you will have to look into. I agree that importance of maintaining safety standards should not be diluted. But this is an incident, which we have taken up with the Indian Air Force. If it were an Airports Authority airport, we would certainly have had direct access to why things went wrong. We have told the Indian Air Force that these things should not be occurring at your airports, wherever they are. After all, it involves not only passenger safety in the case of this but also their own aircraft. So, this should be looked into and given the due attention.

SHRI VIKRAM VERMA: About Gwalior. ... *(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Question No. 82 ... *(Interruptions)*...

SHRI VIKRAM VERMA: I asked about Gwalior.

MR. CHAIRMAN: Question No. 82 ... *(Interruptions)*...Please, let the Question Hour proceed. .... *(Interruptions)*... Please let the Question Hour proceed. ... *(Interruptions)*... Please let the Question Hour proceed. ... *(Interruptions)*... Panyji, take your seat. ... *(Interruptions)*... Please ... *(Interruptions)*... Question No. 82. ... *(Interruptions)*... Please ... *(Interruptions)*...Will you please resume your place? ... *(Interruptions)*...

Strength of employees in PSUs

*82. SHRI TAPAN KUMAR SEN:††
SHRI PRASANTA CHATTERJEE:

Will the Minister of HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES be pleased to state:

(a) the number of permanent employees working in PSUs under the administrative control of this Ministry as on 31st March, 2007 (unit-wise break up); and

(b) the number of contract/casual/contingency workers working in these units as on 31st March, 2007?

THE MINISTER OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI SANTOSH MOHAN DEV): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

Strength of employees in PSUs under the Department of Heavy Industries.

Sl. No.	Name of PSE	No. of Regular/ Permanent employees	No. of Contract/ Casual/ contingency workers
1	2	3	4
1.	Andrew Yule & Co. Ltd. (AYCL)	15797	5121
2.	BBJ Construction Co. Ltd. (BBJ)	93	533
3.	Bharat Heavy Electricals Ltd. (BHEL)	42124	10078
4.	Bharat Heavy Plates & Vessels Ltd. (BHPV)	1512	369
5.	Bharat Pumps & Compressors Ltd. (BPCL)	1214	54
6.	Bharat Wagon & Engineers Co. Ltd. (BWEL)	930	0
7.	Braithwaite & Co. Ltd. (Braithwaite)	525	525
8.	Bridge & Roof Co. Ltd. (B&R)	1449	930
9.	Burn Standard Co. Ltd. (BSCL)	1520	1771
10.	Cement Corporation of India Ltd. (CCI)	1535	1597
11.	Engineering Projects India Ltd.	469	127
12.	Heavy Engineering Corpn. Ltd. (HEC)	3330	2050
13.	Hindustan Cable Ltd. (HCL)	3105	225

††The question was actually asked on the floor of the House by SHRI TAPAN KUMAR SEN.